बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 206 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 02 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली के आईटीओ में शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के बेहद व्यस्त माने जाने वाले आईटीओ इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कैंपस के अंदर मौजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें दफ्तर की दूसरी मंजिल पर देखी गईं जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 9:37 बजे इस अग्निकांड की सूचना मिली। दफ्तर का समय होने के कारण प्रशासन तुरंत हरकत में आया और बिना कोई वक्त गंवाए एक के बाद एक कुल 8 दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया।

दिल्लीवालों को मिली तपिश से राहत- सुबह के न्यूनतम तापमान में आई भारी गिरावट, सामान्य से नीचे पहुंचा पारा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस के बीच सोमवार की सुबह लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई। सोमवार सुबह मौसम के बदले मिजाज के कारण दिल्लीवालों को तेज धूप और लू के थपेड़ों से थोड़ी राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी के लगभग सभी प्रमुख मौसम केंद्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन में कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। इसके अलावा, पालम में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम, 22.8 डिग्री सेल्सियस जबकि लोधी रोड में सामान्य से 3.3 डिग्री कम 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि रिज में न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग चार डिग्री कम है। इसी तरह अयानगर में तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में बारिश दर्ज नहीं की गयी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक91 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डके अनुसार, 0 से 50 के बीच के वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा , 51 से 100 को संतोषजनक , 101 से 200 को मध्यम , 201 से 300 को खराब , 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। आईएमडीके अनुसार, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक नियुक्ति! 5 नए न्यायाधीशों के नाम पर मुहर, जजों की संख्या बढ़कर हुई 37

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) के बुनियादी ढांचे और न्याय प्रक्रिया को गति देने के लिए सोमवार को एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों (जजों) की नियुक्ति की अलग-अलग आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इन पांचों नए जजों के शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या औपचारिक रूप से बढ़कर 37 हो जाएगी।

यह संख्या देश में हाल ही में बढ़ाई गई जजों की कुल स्वीकृत संख्या (38) से अब महज एक कम रह जाएगी। केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा सोमवार सुबह जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनके शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या औपचारिक रूप से 37 हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने एक कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई। न्यायालय में पहले से ही दो पद खाली थे। स्वीकृत संख्या बढ़ाए जाने के बाद शीर्ष अदालत में कुल पद रिक्त छह हो गए थे। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को पांच नियुक्तियों के बाद एक पद रिक्त रहेगा। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 27 मई को इन पांच नामों की सिफारिश की थी और चार दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी गईं।

रणनीतिक रूप से मजबूत हुए दोनों देशों के संबंध, भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता में बोले राजनाथ

नई दिल्ली । भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा व सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सोमवार को नई दिल्ली में दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित हुई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पहले कभी इतने रणनीतिक रूप से एकजुट नहीं रहे। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा सहयोग को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय मजबूती आई है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यासों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों पर जोर दिया। बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान पर चर्चा की। वार्ता का मुख्य फोकस रक्षा व सुरक्षा साझेदारी को मजबूत बनाने, सैन्य बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने, रक्षा उद्योग सहयोग को विस्तार देने व सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों को आगे बढ़ाने पर रहा। इसके अलावा, दोनों पक्ष हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास और सहयोग को और मजबूत करेगी व क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रिचर्ड मार्ल्स की यह यात्रा अक्तूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पहली रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद हुई है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बढ़ती गति को दर्शाती है। भारत के मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय ने भी इस यात्रा को दोनों देशों के रक्षा संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति का प्रतीक बताया है। यात्रा से पहले जारी बयान में रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्तर के सुरक्षा साझेदार हैं और वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को लेकर आशान्वित हैं।

कांग्रेस चिंतन शिविर के समापन में पहुंचे राहुल गांधी, जिलाध्यक्षों के परिवार से मिले, खड़गे का दौरा टला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अजमेर जिले के पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन एवं संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। वाइल्ड रोज रिसॉर्ट में आयोजित इस शिविर में देशभर से आए कांग्रेस पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। शिविर में राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 जिला अध्यक्षों सहित प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने प्रशिक्षण शिविर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जिला अध्यक्षों को संगठन विस्तार, जनसंपर्क और पार्टी की विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। इस दौरान शिविर में शामिल जिला अध्यक्षों के परिवारजन भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। राहुल गांधी ने परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इससे पहले राहुल गांधी सुबह 10:05 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।

किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने राहुल गांधी को पारंपरिक हल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से पुष्कर के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि चिंतन शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश उनका दौरा अंतिम समय में रद्द हो गया। शिविर के समापन के साथ संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

आईटीओ में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के परिसर में लगी आग, दमकलकर्मियों ने पाया गया काबू

नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। विकास मार्ग पर स्थित इमारत की दूसरी मंजिल पर अचानक आग की लपटें उठने लगीं, जिससे हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। आग की भीषणता को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गईं। अग्निशमनकर्मी आग पर काबू पाने और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। आग को काबू कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले बताया जा रहा था कि आग शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में लगी है। लेकिन बाद में इसे लेकर मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा, यह यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय कर्तव्य भवन-2, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली में स्थित है। जबकि आग लगने की घटना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के परिसर में हुई, जो आईटीओ, नई दिल्ली में स्थित है। मंत्रालय ने कहा, आग लगने की घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। इसके अलावा, आग मामूली थी और उस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। किसी भी तरह की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। दमकल विभाग के मुताबिक, आज सुबह लगभग 10 बजे दिल्ली के आईटीओ के पास स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) में आग लगने की घटना के संबंध में सूचना मिली। इस पर तुरंत कदम उठाते हुए मौके पर दमकल की करीब आठ गाड़ियों को भेजा गया। आग पर काबू पा लिया गया है।

कोर्ट में एमसीडी ने झूठ न बोला होता तो न होता हादसा, डेढ़ माह पहले डाला पाप पर पर्दा

नई दिल्ली । दक्षिण दिल्ली के सैदुल्लाजाब इलाके में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास छह मंजिला इमारत ढहने के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। सबसे बड़ा सवाल उस जवाब को लेकर उठ रहा है जो निगम ने हादसे से महज डेढ़ माह पहले दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया था। 13 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के दौरान एमसीडी ने अदालत को बताया था कि संबंधित इमारत में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। लेकिन स्थानीय निवासियों का दावा है कि भवन में लगातार निर्माण और बदलाव का काम जारी था। अब इमारत के ढहने और लोगों की जान जाने के बाद निगम के उस दावे की सच्चाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सैदुल्लाजाब का मामला पहले भी अदालत तक पहुंच चुका था। सितंबर 2025 में इसी क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उस समय निगम ने अदालत को बताया था कि नोटिस

और ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस सहायता और प्रशासनिक कारणों से कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने तब अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई थी और पूछा था कि उनकी निगरानी में अवैध निर्माण कैसे खड़े हो रहे हैं। हादसे वाली इमारत को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार भवन की ऊपरी मंजिलों पर निर्माण गतिविधियां और बदलाव लगातार किए जा रहे थे। वहीं कुछ हिस्सों में कोचिंग सेंटर, कार्यालय और कैंटीन जैसी व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही थीं। इसके बावजूद यदि एमसीडी ने अदालत को बताया कि मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली हाईकोर्ट विभिन्न मामलों में एमसीडी को अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देता रहा है। अदालत ने नोटिस जारी करने के साथ-साथ निरीक्षण, ध्वस्तीकरण और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगते रहे हैं। अब सैदुल्लाजाब हादसे के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि यदि इमारत में वास्तव में निर्माण या संरचनात्मक बदलाव हो रहे थे, तो एमसीडी की निगरानी व्यवस्था उन्हें क्यों नहीं पकड़ सकी। साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि अदालत को दी गई जानकारी और मौके की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर था या नहीं। यही पहलू अब हादसे की जांच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है।

प्रमुख मामले और हाईकोर्ट के निर्देश

19 जनवरी 2026 -जौहरी फार्म, जामिया नगर

अवैध निर्माण से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को तथ्यों की जांच करने और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद भी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अदालत ने एमसीडी को अवैध निर्माणों पर नोटिस जारी करने, निरीक्षण करने और जरूरत पड़ने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मार्च-अप्रैल 2026 -बार-बार दायर याचिकाओं पर टिप्पणी

कुछ मामलों में अदालत ने अवैध निर्माण को बचाने के लिए बार-बार याचिका दायर करने वालों पर जुर्माना लगाया। साथ ही एमसीडी को अवैध निर्माण हटाने और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।

बशीर बद्र के दीवाने

वह एक ऐसा शायर था जिसके दीवानों एवं प्रशंसकों में प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी, कालांतर में डॉ. मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो भी इस फहरिस्त में शामिल थे। दरअसल राजनीतिज्ञों द्वारा अपनी बातों को सार्थक व पसंदीदा प्रस्तुति के लिए गत कुछ दशकों में या तो दुष्यंत कुमार की काव्य पंक्तियां चर्चा में आईं या फिर बशीर बद्र की। भारतीय फिल्म जगत में उनके शेअरों को अपनी बातचीत में उद्धृत करने वालों में मीना कुमारी भी थी, दिलीप साहब भी, देवानंद भी और स्वयं 'बिग बी' भी शामिल थे। मीना कुमारी ने तो एक बार अपने अनेक प्रशंसकों को आटोग्राफ देते वक्त बशीर साहब का वह शेअर अपने हाथ से लिखा, 'उजाले अपनी यादों को' नीचे बशीर का नाम दिया और फिर 'दुआओं के साथ- मीना' के रूप में हस्ताक्षर किए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस महान शायर के जनाजे में इतने कम लोग क्यों आए? उनके एक शेअर 'दुश्मनी जम कर करो/लेकिन यह गुंजायश रहे/जब कभी हम दोस्त जाएं तो शर्मिंदा न हों', का एक बार संसद में बहस के दौरान स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया और बाद में एक बार किसी प्रसंग में श्री मोदी ने भी कह डाला था, 'मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर, मुलाकात कर देंगे।'एक बार संसद में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मिर्जा गालिब के एक शेअर के माध्यम से प्रतिपक्ष-नेता श्रीमती सुषमा स्वराज पर तंज कसा था, 'हमको उनसे है, वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है', तो जवाब में सुषमा जी ने भी बशीर के एक शेअर का सहारा लेते हुए तंज कसा था, 'कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।' हमारे इस कालखण्ड में जिन बड़े शायरों के कलाम एवं गजलें, मुहावरों की तरह आम आदमी व 'इलीट-क्लास' की जुबान पर अक्सर सवार रहते हैं, उनमें बशीर बद्र का नाम पहली पंक्ति में बना रहेगा। वह एक करीबी दोस्त थे, इसलिए मेरा निजी सरमाया भी थे, मगर इसके इलावा इनसे अदबी रिश्ता भी था जो बरसों तक बना रहा। कालजयी शायरी क्या होती है, इसकी कोई मिसाल देखनी हो तो बशीर की शायरी से गुजर कर देखिए। बशीर की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि अपनी अनूठी शैली, बानगी व मौलिक प्रस्तुति के साथ उसने सामयिक मुद्दों को भी बेहद नजाकत के साथ उठाया है। नगरीय एवं कस्बाई हिंसा पर उनका यह तंज अब भी जिक्र में बना हुआ है-जिन दो शायरों का प्रयोग कमोबेश हर राजनीतिज्ञ ने भी किया है, उनमें दुष्यंत के इलावा दूसरा नाम बशीर बद्र का ही है। 91 की उम्र में वह चले गए। सुना था 'डिमेंशिया' सरीखी बीमारियों से पीड़ित लोग लम्बी उम्र तक भी बने रहते हैं। इन दिनों वह 'हल्का-हल्का' बहला भी होने लगे थे, मगर यादों के गलियारे में उस तरह चलने की मशक्कत करने ही लगे थे कि वो बीच सफर में ही लौट गए। इस बार का लौटना अंतिम था और आज वह शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं है। मेरे जेहन में वे पुराने दिन उदास बदली की तरह जिंदगी की उमस से जूझने लगते हैं, जब एक बेहद चहेते व प्यारे अजीज दोस्त के रूप में वह मेरे पुश्तैनी शहर अम्बाला आए थे। हम दो दिन तक उस सरहदी शहर में एक नहर के किनारे घूमते रहे थे। अपनी जिंदगी के ढेरों राज उन दो दिनों में उसने उड़ेले थे। वे 48 घंटे ऐसे बीते जैसे दो-चार पल का सिलसिला हो। मैं, मेरे प्रिय दोस्त एवं उर्दू अदीब मोहनलाल, वहां के बोहिमियन्स क्लब के सूत्रधार प्रो. सत्य प्रकाश, युवा पत्रकार साथी राजमदीप और साथ में बशीर बद्र। दरअसल उन्हीं 48 घंटों की एक शाम हम लोगों ने तय किया कि बशीर के कलाम में हिंदी में उर्दू शायरों को जन्म करने वाली नई पीढ़ी को रूबरू कराया जाए। मोहन लाल मूल रूप से उर्दू व पंजाबी के कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। उन्हीं के मसविरे व पहलकदमी से शब्दलोक प्रकाशन का एक 'बैनर' बुना गया। ये किस्सा लगभग 45 बरस पुराना है। उन दिनों 1100 प्रतियां छापना एक जोखिम भरा प्रयास था। मगर सभी प्रतियां छह महीने में खप गईं। उन्हें खरीदने वाले कमोबेश सभी युवा चेहरे थे। तब मूल्य भी 20 रुपए था और कॉलेजों के पुस्तकालयों के लिए 15 रुपए में। फिर भी पहले संस्करण से जो पैसे बचे, भाई मोहन लाल ने ईमानदारी के साथ उन्हीं दिनों मनी आर्डर (अब पता नहीं प्रचलन में है भी या नहीं) के जरिए भिजवा दिए। मगर सार्थक सोच वाले उदारमना बशीर बद्र ने उसमें 11 रुपए रखे, शेष लौटा दिए। साथ में शुक्रिया अदा किया कि इस कृति के बहाने बड़ी संख्या में हिंदी के पाठक व नवा पीढ़ी उनके प्रशंसकों में शामिल हुए हैं। उनका आग्रह था कि अगला संस्करण शीघ्र छपे। मुझे याद है अम्बाला व गुरुग्राम के वे मुशायरे जिनमें ज्यादातर शायर यही आग्रह करते थे कि उन्हें बशीर से पहले पढ़ा दिया जाए क्योंकि एक बार बशीर शुरू हुए तो फिर श्रोता उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाते रहने की जिद् करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बशीर के जनाजे में सिर्फ 20-30 लोग ही आए। वह कोई राजनेता नहीं थे, जिनकी अंतिम यात्रा में उनके समर्थक कोई भीड़ जुटाते। वह नफीस इंसान भी थे और नफासत एवं खामोशी के साथ 'सुपुर्दे खाक' भी हो गए। अलबशीर बद्र आने वाले लम्बे वक्त तक भारतीयों की जिंदगी में बने रहेंगे। अलविदा बशीर साहब। बशीर बद्र के बारे में बड़ी बात यह नहीं है कि वे बड़े शायर थे। बड़ी बात यह है कि वे ऐसे शायर थे, जिन्हें पढ़कर बहुत से लोगों को पहली बार लगा कि गजल कोई ऊँची मीनार में बैठी हुई अरबी-फारसी की रानी नहीं, शाम के धुंधलके में आपके अपने कमरे में रखी वह छोटी-सी रोशनी है जो बुझती नहीं। उनकी शायरी में इश्क था लेकिन सिर्फ महबूब का इश्क नहीं, उसमें मनुष्य से, स्मृति से, भाषा से, शहर से, दोस्तों से और टूट जाने के बाद भी बची हुई मनुष्यता से इश्क था। बशीर बद्र गजल को कठिन भाषा की जेल से निकालकर आम आदमी के दरवाजे तक लाए थे। बशीर बद्र की सबसे बड़ी क्रांति यही थी कि उन्होंने गजल को आसान बनाया लेकिन हल्का नहीं किया। उनकी भाषा में कोई नकली अकड़ नहीं थी। वे ऐसे शब्द चुनते थे जिन्हें कोई कॉलेज का लड़का भी समझ सके, कोई बूढ़ा श्रोता भी याद रख सके और कोई प्रेम में पड़ा हुआ आदमी तो जैसे अपनी जेब में रख ले। कोई टैंपो या ट्रैक्टर चलाती महिला भी कंठ में बसा ले। यही कारण है कि उनके शेअर किताबों से निकलकर मुशायरों, रेडियो, टीवी, अखबारों, फिल्मों और अब सोशल मीडिया तक पहुंच गए।

लोकतन्त्र में हिंसा निषेध

स्वतन्त्रता के बाद भारत को जो लोकतान्त्रिक प्रणाली हमारी आजादी की लड़ाई के पुरोधा हमें सौंप कर गये है उसमें अहिंसा इसके लिए खाद-पानी का काम करती है। बेशक आजादी की लड़ाई की कई धाराएं थीं जिनमें क्रान्तिकारी व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज का भी उल्लेखनीय योगदान था परन्तु जिस नेतृत्व के पीछे देश के गरीब मजदूर से लेकर संभ्रान्त व कुलीन तक कहे जाने वाले लोग इकट्ठा हुए उसका नाम महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता इसीलिए कहलाये कि उन्होंने आजादी की लड़ाई को जन आन्दोलन में तब्दील कर दिया था। उनकी इस ताकत को सबसे पहले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ही पहचाना और विदेश में आजादी की लड़ाई लड़ते हुए भारतीयों के नाम अपने रेडियो सन्देश में महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' कह कर सम्बोधित किया। राष्ट्रपिता का यह प्रण था कि उनका स्वतन्त्रता आन्दोलन केवल अहिंसक तरीके से ही चलेगा इसी वजह से उन्होंने 1922 के लगभग शुरू हुए असहयोग आन्दोलन में हिंसा भड़क जाने की वजह से उसे वापस ले लिया था जिससे उस समय के कुछ बड़े कांग्रेसी नेता भी असहमत थे।

इन नेताओं में देशबन्धु चितरंजन दास का नाम सबसे प्रमुख था। कहने का मतलब यह है कि गांधी बाबा हमें जो लोकतन्त्र सौंप कर गये है उसमें हिंसा के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं है। यही वजह है कि आजादी मिलने के बाद पहले लोकसभा चुनाव होने से पूर्व ही तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. पं. जवाहर लाल नेहरू ने 26 जनवरी, 1950 को अंगीकृत भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया जिसमें यह प्रावधान था कि हिंसात्मक विचार फैलाने वाला कोई भी राजनीतिक दल भारतीय चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकता। इस संशोधन के बाद ही आजादी मिलते ही प्रतिबन्धित हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के संविधान और चुनावी व्यवस्था के जरिये सत्ता परिवर्तन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। अतः भारत ने जो लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाई उसमें आम नागरिक अपने एक वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी मनपसन्द के राजनीतिक दल की सरकारें स्थापित कर सकते थे। भारत को आजादी मिले 78 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और इस दौरान देश व विभिन्न राज्यों में चुनावों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें बनती-बिगड़ती रही है और इनके बीच हार-जीत होती रही है परन्तु हारने वाली राजनीतिक पार्टी को भी सत्ता में आने वाली पार्टी बराबर का सम्मान देती रही है और उसकी खामियों के खिलाफ पूर्ण अहिंसक तरीके से ही जनता को बताती रही है। लोकतन्त्र में यह लड़ाई निरन्तर चलती रहती है जिसकी वजह से सत्तारूढ़ दल अदलते-बदलते रहते हैं। यह देश मूलतः गांधी का ही देश है और गांधी जी ने आजादी मिलने के मुहाने पर बैठे भारत में एक अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर को दिये गये लम्बे साक्षात्कार में कहा था कि वह अपने विरोधी के विचार उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठा कर सुनना पसन्द करेंगे। लोकतन्त्र कभी भी हिंसात्मक तरीकों से नहीं चलता, बल्कि यह आपसी संवाद व परिसंवाद से चलता है इसीलिए यह उक्ति बनी है कि प्रजातन्त्र में सरकारें बल प्रयोग से नहीं बल्कि इकबाल से चलती है। मगर हम देख रहे है कि प. बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों में हारी हुई तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पर हिंसक हमला हुआ। इतना ही नहीं उनके घायल होने पर जब उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास किया गया तो दो अस्पतालों ने उनका उपचार करने से ही इन्कार कर दिया।

इसकी जितनी निन्दा की जाये वह कम है। सवाल यह है कि यदि चुनावों के दौरान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था तो वह चुनाव परिणामों में बाहर निकल गया इसके बाद उनके खिलाफ भीड़ द्वारा हिंसक कार्रवाई करना उस पश्चिम बंगाल की संस्कृति का ही अपमान है जिसने सैकड़ों की तादाद में स्वतन्त्रता सेनानी दिये हैं। उन पर हमले की घटना की निन्दा विपक्षी नेताओं के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी की है, अतः सत्ता पर काबिज हुई भाजपा सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह चुनाव बाद हिंसा पर काबू रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये और राज्य की राजनीति में नई नजीर पेश करे क्योंकि राज्य में 2021 में जब पिछले चुनाव हुए थे तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोबारा गठित हुई थी और चुनावों के बाद व्यापक हिंसा भी हुई थी जिसे रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी ने अपेक्षित कदम नहीं उठाये थे अतः वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री सुभेन्दु अधिकारी को नई नजीर पेश करते हुए चुनाव हारी हुई पार्टी के नेताओं के लिए शान्तिपूर्ण माहौल पैदा करना चाहिए। वैसे प. बंगाल में 1967 के बाद से राजनीतिक हिंसा का माहौल बनना शुरू हुआ और इसी दौरान इस राज्य से नक्सलवादी आन्दोलन भी निकला जिस पर 70 के दशक में काबू पाया गया लेकिन 1977 से 2011 तक राज्य में वामपंथियों के शासन के दौरान राजनीतिक संस्कृति कहीं न कहीं हिंसा के आवेश में आती रही। इसके बाद ममता दीदी के 15 वर्षों के शासन के दौरान भी इस संस्कृति में बुनियादी फर्क नहीं आ पाया जिसे अब बदले जाने की सख्त जरूरत है। इस संस्कृति को बदलने के लिए राज्य में सक्रिय सभी राजनीतिक दलों को जमीनी स्तर से काम करना चाहिए जिससे आम लोग उस मानसिकता से बाहर आ सकें जिसमें हारे हुए दल के साथ हिंसक व्यवहार करने की प्रवृत्ति छिपी हुई है। श्री बनर्जी लोकसभा के सदस्य है और सदन में अपनी पार्टी के सांसदों के नेता भी है अतः लोकसभा अध्यक्ष का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह उनकी कुशलक्षेम पूछें और राज्य सरकार से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहें क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही इस सदन के सभी सदस्य सांसदों के अधिकारों के संरक्षक हैं। हमारे लोकतन्त्र में शुरू से ही यह परंपरा रही है कि सत्तारूढ़ दल में बैठे नेता विपक्षी नेताओं की कुशलक्षेम का ध्यान रखते आये है जैसे कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी के बीमार होने पर प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में श्री राहुल गांधी से जानकारी प्राप्त की थी। लोकतन्त्र में राजनीति में दुश्मनी नहीं होती बल्कि प्रतिद्वंदिता होती है और उसका आधार वैचारिक होता है।

सम्पादकीय...

आपूर्ति कैसे हो ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से बिजली की खपत कम करने की अपील की है। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। उनका यह आश्वासन सराहनीय है। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। इसी हफ्ते टीवी पर एक शो में बहस के दौरान पत्रकारों ने बताया कि नोएडा में बिजली का भारी संकट चल रहा है। बहुमंजलीय इमारतों में रहने वाले लोग भी बेहाल है। क्योंकि उन्हें पॉवर बैक-अप नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में बिजली कमी को लेकर जगह-जगह जन-आंदोलन चल रहे हैं। जनता की शुरू से ही यह शिकायत रही है कि उनके बिल खपत से कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। जनता ने 'स्मार्ट मीटर' उखाड़ कर फेंकने शुरू कर दिए और आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई। योगी सरकार ने अब इन मीटरों को ना लगाने का फैसला किया है। वैसे तो हर साल गर्मियों में खास कर कर उत्तर भारत में बिजली का संकट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि बांधों में जल का स्तर तेजी से घटता है और नदियां भी सूखने लगती हैं। कारण पहाड़ों पर चल रहे सड़कों के विस्तार ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की है जिससे वर्षा की मात्रा तेजी से गिर गई है। पहाड़ ही क्यों मैदानों में भी जंगलों की अविवेकपूर्ण कटाई ने देश का हरित क्षेत्र खतरनाक स्तर तक कम कर दिया है। जब ज्यादा हरियाली होती है तो वातावरण में नमी पैदा होती है और उससे वर्षा होती है। अगर बिजली की खपत पर लौट कर आएं तो योगी जी की ये चिंता निर्मूल नहीं है। एक जमाने में खस के पर्दे से ही भवन ठण्डे किए जाते थे। फिर कूलर का दौर आया और आज तो घर-घर एसी लग गए है। पर एसी की जितनी खपत आम नागरिक करते है उससे कई गुना ज्यादा सरकारी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान करते है। योगी जी अगर अपने मंत्रालयों के भवनों का औचक निरीक्षण करें तो पाएंगे कि जब अफसर और बाबू कमरों में नहीं होते तब भी वहां कई-कई एसी फालतू चलते रहते है। यही हाल अन्य प्रांतों के सरकारी दफ्तरों का भी होता है। इसलिए बिजली की खपत कम करने की पहल जितनी नागरिकों की तरफ से जरूरी है, उतनी ही शासक वर्ग से भी है। हाइड्रो पॉवर या थर्मल पॉवर की बिजली बनाने की अनेकों सीमाएं हैं। इनसे उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं होता। उल्लेखनीय है कि मई 2026 में उत्तर प्रदेश ने 31,824 मेगावाट का रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरा करने का दावा किया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि शहरों में 24 घंटे और गांवों में 18-22 घंटे बिजली दी जा रही है। केंद्र सरकार भी पूरे देश में 270 से अधिक पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा कर रही है। 2012 के बड़े ब्लैकआउट की तुलना में यह प्रगति प्रभावित करती है लेकिन इन आंकड़ों की चमक जमीनी हकीकत को छुपा नहीं पा रही।

अमेरिका-ईरान तनाव-समझौते और युद्ध के बीच झूलती दुनियाँ ट्रंप की बदलती रणनीति और वैश्विक भू-राजनीति का नया संकट

वैश्विक स्तरपर ईरान और युनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहा वर्तमान टकराव 2026 की सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में से एक बन चुका है। स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि एक तरफ दोनों देश वार्ता की मेज पर बैठे दिखाई देते है, जबकि दूसरी तरफ सैन्य दबाव,आर्थिक प्रतिबंध, नौसैनिक नाकाबंदी और युद्ध की चेतावनियां लगातार जारी है। पूरी दुनियाँ की नजर इस संकट पर टिकी हुई है क्योंकि यह केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, परमाणु प्रसार, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और विश्व अर्थव्यवस्था का प्रश्न बन चुका है। सबसे बड़ा और ताजा अपडेट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ही वार्ताकारों द्वारा तैयार किए गए मसौदा समझौते में नए बदलाव और अधिक कठोर शर्तें जोड़ने की मांग की है। रिपोर्टों के अनुसार व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम, संवर्धित यूरेनियम भंडार और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी भाषा को और सख्त करने का निर्देश दिया है। इससे वह समझौता, जिसे कुछ दिन पहले लगभग अंतिम माना जा रहा था, फिर से अनिश्चितता में फंस गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि वर्तमान संकट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के बयान लगातार बदलते रहे हैं। कभी वे कहते हैं कि समझौता लगभग तैयार है,कभी कहते है कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है,और फिर यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि ईरान अमेरिकी शर्तें नहीं मानता तो सैन्य विकल्प पूरी तरह खुला रहेगा। इस बदलते रुख ने न केवल तेहरान बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों को भी असमंजस में डाल दिया है।अमेरिका की मुख्य मांगें अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और कठोर दिखाई दे रही हैं। वाशिंगटन चाहता है कि ईरान स्थायी रूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने की कानूनी और अंतरराष्ट्रीय गारंटी दे। इसके अलावा ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम के बड़े भंडार को या तो नष्ट किया जाए या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में सौंप दिया जाए। अमेरिका यह भी चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह खुला रहे, जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा और बिना किसी टोल के हो तथा ईरान अपनी मिसाइल और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों पर भी नियंत्रण स्वीकार करे। साथियों, दूसरी तरफ ईरान का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने, अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों को वापस पाने और क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में अपनी भूमिका को मान्यता दिलाने की मांग कर रहा है। यही कारण है कि बातचीत बार-बार आगे बढ़ने के बाद फिर अटक जाती है। पिछले कुछ दिनों में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार कई बैठकों में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी शर्तों पर तीखी आपत्ति जताई। कुछ मौकों पर बातचीत बीच में रुक गई और ईरानी पक्ष ने असंतोष व्यक्त करते हुए बैठक छोड़ दी। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से वार्ता समाप्त होने की घोषणा नहीं की है। ओमान और अन्य मध्यस्थ देशों के माध्यम से संवाद जारी है।पूरे संकट का सबसे संवेदनशील मुद्दा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। दुनियाँ के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से गुजरता है। अमेरिका चाहता है कि यह मार्ग पूरी तरह खुला और मुक्त रहे, जबकि ईरान इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और प्रशासनिक भूमिका को स्वीकार करवाना चाहता है। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर मतभेद बने हुए हैं। स्थिति को और गंभीर बनाने वाली घटना वह थी जब अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जा रहे एक कार्गो जहाज को रोकने के लिए मिसाइल कार्रवाई की।अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जहाज नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि ईरान इसे उकसावे की कार्रवाई बता रहा है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि बातचीत चलने के बावजूद सैन्य टकराव का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। साथियों, युद्ध की संभावना को लेकर दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों में मतभेद हैं। हालांकि अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देश पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। फिर भी किसी गलत सैन्य गणना, ड्रोन हमले, समुद्री झड़प या परमाणु विवाद के कारण स्थिति अचानक नियंत्रण से बाहर जा सकती है। वर्तमान हालात को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि क्षेत्र «न युद्ध, न शांति» की स्थिति में है।इसी बीच इजराइल की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने समझौते के मसौदे को इजराइल सहित अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ साझा किया है ताकि किसी संभावित समझौते पर सटीकता से क्षेत्रीय सहमति बनाई जा सके। साथियों इस पूरे संकट का एक बड़ा आयाम महाशक्तियों की राजनीति भी है। चाइना और रूस दोनों विभिन्न स्तरों पर ईरान के साथ जुड़े हुए है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ता है तो यह केवल पश्चिम एशिया का संकट नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रश्न बन जाएगा। रूस और चीन खुले सैन्य हस्तक्षेप से बच सकते है,लेकिन कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन के माध्यम से समीकरण को जटिल बना सकते हैं।भारत के लिए यह संकट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडिया अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करता है। यदि संघर्ष बढ़ता है और होर्मुज में यातायात बाधित होता है तो सबसे पहला प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि गंभीर संघर्ष की स्थिति में तेल 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इससे भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ेगा और चालू खाते का दबाव बढ़ सकता है।तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर पेट्रोल, डीजल और परिवहन लागत पर पड़ेगा। परिवहन महंगा होने से खाद्य पदार्थों से लेकर औद्योगिक वस्तुओं तक लगभग हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों पर भी दबाव बढ़ेगा क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन सकती है।भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तेल आयात पर निर्भर कंपनियां, एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र विशेष दबाव में आ सकते हैं। इसके विपरीत ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र की कुछ कंपनियों को सटीकता से लाभ भी मिल सकता है। साथियों , खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। यदि संघर्ष व्यापक रूप लेता है तो भारत को फिर से बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है, जैसा अतीत में विभिन्न संकटों के दौरान देखा गया था।वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा खतरा ऊर्जा संकट का है। यदि होर्मुज में व्यवधान आता है तो केवल तेल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। यूरोप पहले से ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्नों से जूझ रहा है और नया संकट वहां की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।विश्व शेयर बाजारों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी बाजारों में गिरावट, यूरोप में ऊर्जा आधारित कंपनियों पर दबाव और एशियाई बाजारों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर जाते है, इसलिए सोने और अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों में तेजी की संभावना बढ़ जाती है।समुद्री व्यापार भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। यदि जहाजों की आवाजाही पर खतरा बढ़ता है तो बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई लागत बढ़ जाएगी। इससे वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और वस्तुओं की कीमतें विश्व स्तर पर बढ़ सकती हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अमेरिका और ईरान दोनों एक-दूसरे पर दबाव बनाते हुए बेहतर सौदा हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप का बार-बार बदलता रुख कुछ विश्लेषकों को भ्रमित करने वाला लगता है, लेकिन दूसरी व्याख्या यह भी है कि वे अधिकतम दबाव और अधिकतम सौदेबाजी की रणनीति अपना रहे हैं। दूसरी ओर ईरान भी पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं है क्योंकि ऐसा करना उसकी घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय प्रतिष्ठा के लिए कठिन होगा।आज की स्थिति में पूर्ण युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और बातचीत अभी भी जारी है। लेकिन यह भी सच है कि हालात बेहद नाजुक हैं। किसी भी गलत सैन्य कार्रवाई, होर्मुज में नई घटना, परमाणु मुद्दे पर गतिरोध या क्षेत्रीय समूहों की गतिविधियों से संकट अचानक भड़क सकता है। इसलिए दुनिया की निगाहें आने वाले दिनों में होने वाली अमेरिका- ईरान वार्ताओं, ट्रंप द्वारा मांगी गई नई शर्तों और तेहरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। फिलहाल पूरा विश्व युद्ध और समझौते के बीच झूलते इस संकट के अगले अध्याय का इंतजार कर रहा है।

बालेन्द्र शाह ने ब्रिटेन को निमंत्रित कर करवाई अपनी जगहँसाई

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर चल रहा पुराना सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया भू-राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की चौंकाने वाली और कई मायनों में अपरिपक्व बयानबाजी बनी है। संसद में उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिसने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी। हालात इतने असहज हो गए कि कुछ ही घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। और विडंबना देखिए, भारत को घेरने की कोशिश में दिया गया बयान नेपाल में ही प्रधानमंत्री के लिए भारी पड़ गया। विपक्ष, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राजदूत और सीमा विशेषज्ञ तक उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनसे सबूत, स्पष्टीकरण, यहां तक कि माफी की मांग होने लगी। सीमा विवाद पर राजनीतिक परिपक्वता दिखाने के बजाय बालेन्द्र शाह की टिप्पणियां ऐसी साबित हुईं जिन्होंने नेपाल की आधिकारिक स्थिति को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। हम आपको बता दें कि नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने दोनों देशों से तथ्यों का अध्ययन कर मित्रवत तरीके से विवाद सुलझाने की अपील की। उधर, नेपाल में विपक्षी दलों और पूर्व राजनयिकों ने बालेन्द्र शाह की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नेपाली कांग्रेस की बसना थापा और अन्य नेताओं ने संसद के अभिलेखों से बयान हटाने की मांग की। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही। नेपाल के पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य और दीप कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने भी प्रधानमंत्री की बातों को तथ्यात्मक आधार से रहित बताया। इस प्रकार बालेन्द्र शाह का बयान भारत से अधिक नेपाल के भीतर ही विवाद का विषय बन गया। दरअसल, सीमा विवाद का केंद्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र है। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के अनुसार काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसके पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाली भूभाग है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम लिपुलेख दर्रे के नीचे स्थित स्रोतों से होता है और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कालापानी क्षेत्र लंबे समय से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा है। यही मूल विवाद दोनों देशों के दावों की जड़ में है। हम आपको बता दें कि विवाद को हाल में उस समय नया मोड़ मिला जब नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताते हुए भारत और चीन दोनों को कूटनीतिक नोट भेजा। भारत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से लगातार संचालित हो रही है और यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। भारत ने यह भी दोहराया कि एकतरफा तरीके से क्षेत्रीय दावों का विस्तार न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही स्वीकार्य है। उधर, बालेन्द्र शाह के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का आशय यह नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। मंत्रालय के अनुसार सीमा के कुछ हिस्सों में सीमा स्तंभों की कमी, दशगजा क्षेत्र और सीमापार भूमि उपयोग जैसी व्यावहारिक समस्याओं के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जहां दोनों ओर के लोग एक-दूसरे की जमीन का उपयोग करते रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि दोनों देश कूटनीतिक बातचीत, तकनीकी सर्वेक्षण और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सबसे अधिक हैरानी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के उस सुझाव पर हुई जिसमें उन्होंने सीमा विवाद के समाधान में ब्रिटेन की भागीदारी की बात उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान सीमाओं की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल से जुड़ी है, इसलिए ब्रिटेन को भी इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। यह प्रस्ताव न केवल व्यावहारिक दृष्टि से कमजोर माना गया बल्कि नेपाल के भीतर भी इसे अपरिपक्व और अनावश्यक बताया गया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हमेशा द्विपक्षीय ढांचे में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में तीसरे पक्ष को बीच में लाने की बात कूटनीतिक परंपराओं और स्थापित समझ से मेल नहीं खाती। इसके अलावा, सीमा विवाद जैसे संवेदनशील और पूर्णतः द्विपक्षीय विषय में ब्रिटेन को शामिल करने का सुझाव बालेन्द्र शाह की कूटनीतिक नासमझी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन था जिसने कई जानकारों को हैरान कर दिया। भारत दशकों से स्पष्ट करता आया है कि वह अपने किसी भी द्विपक्षीय विवाद में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखल को स्वीकार नहीं करता, चाहे मामला पाकिस्तान का हो, चीन का हो या नेपाल का। ऐसे में ब्रिटेन को बातचीत की मेज पर बुलाने का प्रस्ताव शुरू से ही अव्यावहारिक और वास्तविकताओं से कटा हुआ नजर आया। जिस देश ने दो शताब्दियों पहले उपमहाद्वीप छोड़ दिया, उसे आज की सीमा वार्ताओं में घसीटने की कोशिश को कई पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक अपरिपक्वता बताया। दिलचस्प यह है कि बालेन्द्र शाह की इस टिप्पणी पर केवल नेपाल में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के रणनीतिक और दक्षिण एशियाई मामलों पर नजर रखने वाले हलकों में भी हैरानी जताई गई और इसे अव्यावहारिक सोच का उदाहरण माना गया। कूटनीति की दुनिया में जहां गंभीरता, तैयारी और यथार्थवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है, वहां बालेन्द्र शाह का यह सुझाव कई लोगों को ऐसा लगा मानो किसी जटिल अंतरराष्ट्रीय विवाद के समाधान के लिए इतिहास की धूल झाड़कर ऐसे पात्रों को मंच पर बुलाने की कोशिश की जा रही हो जिनकी अब उस प्रक्रिया में कोई वास्तविक भूमिका ही नहीं बची है। देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से लिपुलेख क्षेत्र का महत्व अत्यंत गहरा है। यह भारत, नेपाल और चीन के त्रिसीमा क्षेत्र के निकट स्थित है। यह केवल धार्मिक यात्रा का मार्ग नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र में संपर्क, निगरानी और रणनीतिक पहुंच का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। चीन की बढ़ती सक्रियता और हिमालयी क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच यह इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और भी संवेदनशील हो गया है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़ा कोई भी राजनीतिक बयान केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके व्यापक सामरिक प्रभाव भी होते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान इसी कारण अधिक विवादास्पद बन गया। बिना पर्याप्त तैयारी और तथ्यों की मजबूत प्रस्तुति के ऐसे संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी करना न केवल कूटनीतिक भ्रम पैदा करता है बल्कि अपने ही देश की आधिकारिक स्थिति को कमजोर भी कर सकता है। यही कारण है कि उनकी टिप्पणियों के तुरंत बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा और देश के अनेक राजनीतिक तथा कूटनीतिक विशेषज्ञों ने उनकी आलोचना की। बहरहाल, यह पूरा प्रकरण एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े मतभेद अवश्य हैं, लेकिन दोनों देशों ने बार-बार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे समय में भावनात्मक या चौंकाने राजनीतिक बयान समाधान का रास्ता नहीं खोलते, बल्कि अनावश्यक भ्रम और विवाद को जन्म देते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की हालिया टिप्पणियां इसी का उदाहरण बन गई है, जहां भारत पर निशाना साधने की कोशिश से अधिक नुकसान उन्हें अपने ही देश के राजनीतिक और

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, [illegible], दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/[illegible])

नेपाली नागरिकों से करोड़ों की ठगी का अंतरराष्ट्रीय रैकेट ध्वस्त, 453 पीड़ितों को सकुशल भेजा गया स्वदेश

कुशीनगर।

जनपद पुलिस ने एक बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई करते हुए नेपाल के नागरिकों को नौकरी, पढ़ाई और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी का शिकार बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना कसया, स्वाट टीम, सर्विलांस सेल, एसटीएफ गोरखपुर तथा जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 9 नेपाली नागरिक और एक भारतीय शामिल है। इस दौरान 453 नेपाली नागरिकों को सकुशल मुक्त कराकर उनके देश वापस भेजा गया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में संचालित इस विशेष अभियान की शुरुआत तब हुई जब लगातार ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं कि नेपाल के नागरिकों को बेहतर नौकरी, उच्च शिक्षा और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आकर्षक आय का सपना दिखाकर कुशीनगर बुलाया जा रहा है। यहां किराये के मकानों में ठहराकर उनसे विभिन्न मदों में धन वसूला जाता था तथा बाद में उन्हें ठगी का शिकार बनाकर वापस नेपाल भेज दिया जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मुकदमा दर्ज कराते हुए कई विशेष टीमों का गठन किया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गिरोह कूटरचित आधार कार्ड, बॉन्ड पेपर और अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर पीड़ितों का विश्वास जीतता था। गिरोह के सदस्य विशेष रूप से कम पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाते थे तथा उनसे बड़ी रकम ऐंठकर आर्थिक शोषण करते थे।

शनिवार को देर रात शुरू हुआ यह विशेष ऑपरेशन भोर तक चला। कार्रवाई को पूरी गोपनीयता और पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया ताकि किसी प्रकार की अफवाह या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से नौ फर्जी आधार कार्ड, 60 बॉन्ड पेपर, एक लैपटॉप, सोने-चांदी जैसे दिखने वाले आभूषण, भारतीय एवं नेपाली मुद्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की है।

इस पूरे अभियान में नेपाल दूतावास का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने नेपाली एंबेसी से संपर्क स्थापित किया, जिसके बाद दूतावास के प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में अभियान संचालित किया गया। नेपाल दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी प्रकाश मल्ल ने कुशीनगर पुलिस और जिला प्रशासन की सराहना करते हुए नेपाली नागरिकों की सुरक्षा एवं सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में पीड़ितों को सुरक्षित मुक्त कराना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय इस ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करना जनपद पुलिस की पेशेवर कार्यशैली और प्रभावी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है।

संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत

कप्तानगंज(कुशीनगर)।

कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के अहिरौली थाना अन्तर्गत ग्राम सभा बरडीहा के एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे लेकर पो स्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मामला में प्रेम प्रसंग से जुड़े होने की संभावना है। परिजनों के अनुसार शनिवार की देर रात बरडीहा निवासी संदीप यादव उम्र (22) भोजन के उपरांत घर से कुछ दूर स्थित मोबाइल टावर की तरफ गया था, कुछ समय के उपरांत मृतक संदीप के मोबाइल से उसके मित्र विशाल यादव के मोबाइल पर काल कर के बताया गया कि संदीप गांव के बाहर पुलिया के समीप घायल अवस्था में पड़ा है

इसकी सूचना मिलते ही चाचा और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। जहां संदीप पुल के रेलिंग के पास गम्भीर अवस्था में पड़ा था। तथा उसका मोबाइल उसी के सीने पर मिला, परिजनों ने आनन फानन में उसे गोरखपुर मेडिकल कालेज ले गये जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों की लिखित सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। जब कि मृतक के भाई का कुछ बर्ष पहले कैंसर से मौत हो चुकी है। पूरे परिवार के भरण पोषण की सभी जिम्मेदारी इस के कन्धे पर था। ग्रामीणों में चर्चा है कि मामला कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा तो नहीं है। सतर्कता के तौर पर गांव में पुलिस गस्त कर रही हैं तथा जांच हेतु फोरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर नमूना ली है। अहिरौली थानाध्यक्ष प्रविंद्र राय ने बताया कि पीएम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

शहर में पुलिस कप्तान का रूट मार्च : कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजारों में भारी बल के साथ खुद उतरे एसपी अभिजीत आर. शंकर

देवरिया। जनपद में शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने तथा आम नागरिकों के भीतर सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में रविवार को पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने स्वयं कमान संभालते हुए भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त किया। इस रूट मार्च के जरिए पुलिस कप्तान ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पिकेट पॉइंट की मुस्तैदी का जमीनी स्तर पर व्यापक निरीक्षण किया।पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी और कोतवाली पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों व चौराहों का रुख किया। इस दौरान टीम ने सुभाष चौक, मालवीय रोड, नगर पालिका रोड, कॉपरेटिव चौराहा, रामलीला मैदान और हनुमान मंदिर चौराहा सहित प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और मुख्य मार्गों पर सघन भ्रमण किया। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की दृश्यता बढ़ाकर आमजन में विश्वास पैदा करना रहा। चक्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने केवल सुरक्षा घेरे का निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि सड़कों पर आम नागरिकों, स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों, महिलाओं और युवाओं से सीधा संवाद भी स्थापित किया। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और सुरक्षा से जुड़े उनके महत्वपूर्ण सुझावों को नोट किया। कप्तान ने व्यापारियों और नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा और सहायता के लिए चौबीसों घंटे विधिक रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि सामान्य दिनों या त्योहारों के दौरान किसी भी स्तर पर असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध अत्यंत कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था का गहनता से अवलोकन करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मौके पर मौजूद अधीनस्थ अधिकारियों और कोतवाली प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

सीडीओ की मैराथन चौपाल, परखीं विकास योजनाएं, सरकारी योजनाओं से वंचित पात्रों को जोड़ने के निर्देश

देवरिया।

ग्रामीण विकास की योजनाओं को रफ्तार देने और शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देशानुसार, रविवार की छुट्टी के बावजूद मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने विकास खंड बनकटा क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने ब्लॉक मुख्यालय सहित क्षेत्र के बखरी, हाटा, बगरूआ तथा सिकटिया दीनाचक गांवों में आयोजित विभिन्न जन-चौपालों की अध्यक्षता की। इस दौरान सीडीओ ने ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ आमने- सामने बैठकर जनकल्याणकारी योजनाओं की वास्तविक प्रगति खंगाली और स्थानीय जनसमस्याओं के निस्तारण को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। बनकटा क्षेत्र में आयोजित इन चौपालों में मुख्य विकास अधिकारी ने बुनियादी ढांचे से जुड़े बुनियादी विकास कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्राथमिक एवं उच्च

प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प, पंचायत भवनों के सुचारु संचालन, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति तथा निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आच्छादन बढ़ाने की रणनीति पर विमर्श हुआ। सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मनरेगा जॉब कार्ड धारकों, वृद्ध व विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्रों में से जो भी परिवार अभी तक किन्हीं कारणों से राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं, उन्हें विधिक प्रक्रिया पूरी कर तत्काल इस सुविधा से जोड़ा जाए। इसके साथ ही, चौपालों में डिजिटल और आधुनिक योजनाओं जैसे फैमिली आईडी, फॉर्मर आईडी और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रगति की जमीनी हकीकत परखी गई। सीडीओ ने कृषि और राजस्व विभाग के कर्मियों को निर्देशित किया कि चारागाह की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त रखने और अमृत सरोवरों के रखरखाव में कोई लापरवाही न बरती जाए। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नए स्वयं सहायता समूहों के गठन और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर बल दिया

जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार की छुट्टी के दिन बखरी, हाटा, बगरूआ और सिकटिया दीनाचक पहुंचे सीडीओ राजेश कुमार सिंह

फैमिली आईडी, फॉर्मर आईडी और पीएम सूर्यघर योजना की ब्लॉक स्तर पर की सघन समीक्षा

गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कड़े रुख में कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता या हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सभी विभागीय अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित कराएं। इस मैराथन समीक्षा के दौरान खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रहीं।

बीएड प्रवेश परीक्षा- डीएम व एसपी ने परीक्षा संचालन एवं व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। रविवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नवजीवन इंटर कॉलेज, पटहेरवा सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा कक्षों, प्रवेश द्वारों, सीसीटीवी कैमरों, मेटल डिटेक्टर, पेयजल व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों एवं तैनात अधिकारियों से परीक्षा संचालन संबंधी जानकारी प्राप्त की तथा अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने तथा परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता बनाए रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा को पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन के अनुसार जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन जांच की व्यवस्था की गई, जबकि परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। जिला प्रशासन ने दावा किया कि परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराई जा रही है।

सीनियर वकीलों को दलीलें रखने की अनुमति नहीं, सिर्फ यंग लॉयर को ही- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने सोमवार (1 जून, 2026) को कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बेंच के सामने न तो सीनियर एडवोकेट्स को केस लिस्ट करवाने के लिए उल्लेख करने देंगे और न ही सुनवाई के दौरान दलीलें रखने की अनुमति देंगे. उन्होंने कहा कि वह इस दौरान सिर्फ युवा वकीलों और 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' को अपनी बेंच के समक्ष दलीलें रखने की अनुमति देंगे. सोमवार की सुबह जस्टिस विक्रम नाथ ने घोषणा की थी कि सीनियर वकीलों को दलीलें रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जस्टिस संजय करोल ने भी यही रुख अपनाया. 1 जून से 12 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां है. सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मावकाश को अब आंशिक न्यायालय कार्य दिवस कहा जाता है. इस साल इस अवधि के दौरान हर हफ्ते तीन से चार बेंच सुनवाई करेंगी. जस्टिस विक्रम नाथ ने सुनवाई शुरू होते ही कहा, मेरी अदालत में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने जस्टिस पी. बी. वराले की सदस्यता वाली बेंच की अगुवाई करते हुए यह कहा. जब एक सीनियर एडवोकेट ने एक मामले का उल्लेख करने की कोशिश की तो जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि वह आंशिक न्यायालय कार्य दिवसों के दौरान अपनी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध मामलों में वरिष्ठ वकीलों को न तो मामले का उल्लेख करने देंगे और न ही दलीलें रखने की अनुमति देंगे. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि वह इस अवधि के दौरान सिर्फ युवा वकीलों और 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' को अपनी बेंच के समक्ष दलीलें रखने की अनुमति देंगे. जब एक वरिष्ठ वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें मामले में आज दलीलें रखने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी तो जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, आप एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या निर्देश देने वाले वकील को बुलाइए, हम उन्हें सुनेंगे लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नहीं. बेंच ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हो रहे हैं, उन्हें खारिज नहीं किया जाएगा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामान्य कार्यदिवस फिर शुरू होने के बाद जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक अन्य बेंच ने भी कहा कि आंशिक न्यायालय कार्य दिवसों के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मामलों का उल्लेख करने या दलीलें रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जस्टिस नरसिम्हा ने अदालत कक्ष में मौजूद वकीलों से कहा, हम आज के लिए ही इसकी अनुमति दे रहे हैं लेकिन कल से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दलीलें रखने या मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर कनिष्ठ अधिवक्ता मामलों में दलीलें रखते हैं तो नोटिस जारी होने की संभावना अधिक है और अगर वरिष्ठ अधिवक्ता दलीलें रखते हैं तो मामला खारिज होने की संभावना अधिक है. जस्टिस संजय करोल ने भी इसी तरह की टिप्पणी की. उन्होंने जस्टिस ए. जी. मसीह की सदस्यता वाली बेंच की अध्यक्षता करते हुए अपनी बात रखी.

धर्मेंद्र प्रधान को राजधर्म निभाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए - कांग्रेस

सीबीएसई मार्किंग विवाद

अक्षमता की मिसाल हैं मंत्री प्रधान- जयराम रमेश

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा और कहा कि अपना राजधर्म निभाते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि प्रधान अहंकार और अक्षमता की जीती-जागती मिसाल बन चुके हैं।

रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, ओएसएम प्रणाली में साइबर सुरक्षा संबंधी खामियों से इनकार करने के बाद अब सीबीएसई ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया है कि सिस्टम से समझौता किया गया था। लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्टर कोएम्प्ट के खिलाफ वह क्या कार्रवाई करने जा रहा है? उन्होंने दावा किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय में कोएम्प्ट से लाभान्वित होने वालों को पहले से अंदाजा था कि कोएम्प्ट इस काम के लिए योग्य साबित नहीं होगी। रमेश का कहना है, सीबीएसई ने अगस्त 2025 के अपने उन वेंडर्स को प्रबंधित करने का अधिकार अपने पास रखा था, जो काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल रहते। लेकिन सितंबर में सीबीएसई ने एक शुद्धिपत्र जारी कर वेंडर्स को प्रतिबंधित करने का अपना ही अधिकार हटा लिया।

उन्होंने कहा, यह कोएम्प्ट बचाने की सरकार समर्थित कोशिश दिखाई देती है, जो कोएम्प्ट को आधिकारिक रूप से अनुबंध मिलने से पहले ही शुरू हो गई थी। रमेश ने कहा, देश आखिर कब तक ऐसे मंत्री प्रधान को बर्दाश्त करेगा, जिनके मंत्रालय ने निविदा प्रक्रिया में ऐसी अकल्पनीय अनियमितताओं को न केवल होने दिया, बल्कि उन्हें संरक्षण भी दिया, जिसकी कीमत लाखों छात्रों को अपनी मानसिक शांति खोकर चुकानी पड़ी? मंत्री प्रधान अहंकार और अक्षमता की जीती-जागती मिसाल बन चुके हैं, जो राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से ऊपर अपने राजनीतिक एजेंडे को रखने पर अड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी खुद को या अपने सहयोगियों को नैतिकता और शुचिता के किसी मानक पर कसने के लिए नहीं जाने गए हैं..., लेकिन मंत्री प्रधान को अपना राजधर्म निभाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।

सीएम रेखा का बड़ा एक्शन- दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल 40 से ज्यादा डॉक्टरों और अधिकारियों का ट्रांसफर

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 40 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सीपीए में कार्यरत 40 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार सीपीए में एचओओ (हेड ऑफ ऑफिस) डॉ. विनोद कुमार रंगा सहित 10 डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया है। वहीं पैरामेडिकल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 19 कर्मचारियों का तबादला किया गया है। इनमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवर शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्तर के 10 कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। मानव संसाधनों की समीक्षा के दौरान सीपीए में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति का आकलन किया गया। साथ ही ऐसे कर्मचारियों की जानकारी भी संकलित की गई है जो सीपीए के वेतनमान पर हैं, लेकिन अन्य कार्यालयों में कार्यरत है, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा अन्य स्टाफ को भी सीपीए से हटाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सीपीए दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रियों की खरीद एवं आपूर्ति का कार्य संचालित होता है। इस व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने के लिए विभिन्न अस्पतालों और विभागों से अनुभवी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से 12 चिकित्सा अधिकारियों की सीपीए में तैनाती की गई है। इनमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी और सीएमओ स्तर के अधिकारी शामिल है। सरकार का मानना है कि इनकी तैनाती से खरीद, भंडारण, आपूर्ति और प्रशासनिक कार्यों को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभागीय कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। प्रोजेक्ट ब्रांच, केयरटेकिंग ब्रांच, स्टोर एवं परचेज ब्रांच, कंप्यूटर सेल, मोबाइल हेल्थ स्कीम, पीजीएमएस, आरटीआई, नहल्ड मट्स, हेल्थ मेला, अस्पताल समन्वय और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा स्टोर एवं परचेज ब्रांच तथा सीपीए से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक इकाई को आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराना और संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद एवं आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ हो तथा दिल्लीवासियों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत 6 जून को भारत लौटेंगे

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, इंस्टा फॉलोअर 2 करोड़ पार

नई दिल्ली ।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को भारत लौटेंगे। इसके बाद वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। दिपके ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट 'कॉकरोच इज बैक' पर दी है।

कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 30 साल के अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिजीत 2020 से 2022 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अभिजीत आप के लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार का मटेरियल बनाते थे। एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि उन्होंने निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिरता के लिए आप छोड़कर बोस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। एडमिशन मिल गया, तो वे अमेरिका शिफ्ट हो गए।अभिजीत किसान आंदोलन से लेकर महंगाई जैसे राजनीतिक मुद्दों पर द्वू अकाउंट पर केंद्र सरकार और पीएम पर निशाना साधते रहे हैं।

ईरान ने अमेरिका से सीजफायर वार्ता रोकी- होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी; लेबनान पर हमलों के विरोध में फैसला

तेल अवीव । ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, तेहरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में इजराइली हमले नहीं रुकते, तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बनाए रखना सीजफायर की अहम शर्तों में शामिल था। लेकिन अब लेबनान समेत कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। ईरान ने गाजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और लेबनानी क्षेत्र से इजराइली सेना की पूरी वापसी की मांग की है। तेहरान का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर उसकी और उसके सहयोगियों की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक बातचीत दोबारा शुरू नहीं होगी। तस्नीम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान और उसके सहयोगी होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद करने और अन्य मोर्चों को एक्टिव करने के ऑप्शन पर भी विचार कर रहे हैं। इनमें लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में स्थित बाब अल-मंदेब स्ट्रेट भी शामिल है। ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल का कब्जा- इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। यह पिछले 26 साल में इजराइल की लेबनान में सबसे बड़ी घुसपैठ है।

इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग- फ्रांस ने लेबनान में इजराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है।

ट्रम्प बोले- ईरानी सेना के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं- ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका ने ईरानी सेना पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं की, जितनी वह दूसरे देशों की सेनाओं के खिलाफ करता रहा है।

ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं- ईरान ने कहा है कि जब तक यह भरोसा नहीं हो जाता कि उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है, तब तक अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

अमेरिका ने ईरान जा रहे जहाज को रोका- अमेरिका ने ईरान की ओर जा रहे एक और मालवाहक जहाज को रोक दिया। 17 अप्रैल से अब तक अमेरिका 6 जहाजों को ईरान जाने से रोक चुका है।

अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेगी, हिजबुल्ला के खतरे पर बोला इस्राइल

नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस्राइल के राजदूत रियूवेन अजार ने इस्राइल-लेबनान तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने बिना किसी उकसावे के फिर इस्राइल पर हमला किया। अजार के मुताबिक युद्धविराम लागू होने के बाद भी हिजबुल्लाह की ओर से 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिनमें 12 से अधिक इस्राइली नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई है। रियूवेन अजार ने कहा कि हिजबुल्लाह से ड्रोन और यूएवी का बड़ा खतरा बना हुआ है। इसी कारण इस्राइल रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण मजबूत कर रहा है ताकि इन खतरों को रोका जा सके। उन्होंने साफ कहा कि इस्राइल अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। इस्राइली राजदूत ने कहा कि उनका लेबनान सरकार से कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि लड़ाई उन कट्टरपंथी ताकतों से है जो इस्राइल को खत्म करने की बात करती है।

इंडिया गठबंधन के नेता आठ जून दिल्ली में कर सकते हैं बैठक, बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर चर्चा संभव

नई दिल्ली । विपक्षी गठबंधन इंडिया के बड़े नेता आठ जून को दिल्ली में एक अहम बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाना और विपक्षी एकता को मजबूत करना है। यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने की संभावना है। इसमें लगभग 15 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। यह बैठक हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद हो रही है। इन चुनावों में गठबंधन के दो मुख्य दल, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके को हार का सामना करना पड़ा है। ये दोनों दल क्रमशः पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हो गए हैं।

बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की उम्मीद है। गठबंधन के समीकरणों में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके से नाता तोड़कर टीवीके का साथ दिया है। इस वजह से डीएमके के बैठक में शामिल होने की संभावना कम है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को साथ लाने की कोशिशें जारी हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी ने पहले ही गठबंधन से सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली है, इसलिए वह भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। बैठक में विपक्षी दलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हो रहे कथित हमलों का मुद्दा उठा सकती है और अन्य दलों का समर्थन मांग सकती है। इससे पहले गठबंधन की आखिरी आधिकारिक बैठक एक जून 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी। इसके बाद सात अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने अपने आवास पर एक खास डिनर दिया था। उस समय 25 से ज्यादा दलों के लगभग 50 नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे मुद्दे पर चर्चा की थी। विपक्षी दल संसद सत्रों के दौरान भी एकजुट रहे हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस लाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। हालिया चुनावी नतीजों ने विपक्ष को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। इंडिया गठबंधन का गठन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए को चुनौती दी जा सके।

उद्योगपति अरुण लखानी के बीजेपी उम्मीदवार बनने पर उठे सवाल, संजय राउत बोले- वे आरएसएस के पुराने समर्थक

मुंबई । शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सोमवार को उद्योगपति अरुण लखानी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए लखानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राउत ने कहा कि लखानी का नामांकन कोई अजीब बात नहीं है। उन्होंने लखानी को एक सज्जन व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि लखानी हमेशा से आरएसएस का समर्थन किया है। अरुण लखानी के बेटे सारंग की शादी एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से होने वाली है। भाजपा ने लखानी को वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि लखानी शुरू से ही विदर्भ के उन लोगों की सूची में शामिल है जिन्होंने आरएसएस को हर तरह से मजबूती दी है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र से संसद में ऐसे कई नेता हैं जिनकी जड़ें आरएसएस में है। लखानी कभी कांग्रेस या एनसीपी (एसपी) में नहीं रहे। विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख एक जून है। दो जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। चार जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटों की गिनती 22 जून को होगी। यह चुनाव 16 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में हो रहे हैं। इनमें सोलापुर, अहमदनगर, ठाणे, जलगांव, सांगली-सतारा, नांदेड़, यवतमाल, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नासिक, वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली, अमरावती, उस्मानाबाद-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली और औरंगाबाद-जालना शामिल हैं। नागपुर सीट पर उपचुनाव भी होगा। इन चुनावों में स्थानीय निकायों के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। संजय राउत ने प्राजक्त तनपुरे के नामांकन को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तनपुरे ने पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। राउत ने तनपुरे से कहा कि वे विकास कार्य का बहाना बनाकर भाजपा का इस्तेमाल करने का नाटक बंद करें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए।

पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी अब सिर्फ नए आने वाले नेताओं के लिए दरी बिछाने और चाय के कप उठाने तक रह गई है। राउत ने दावा किया कि भाजपा के ज्यादातर बड़े नेता दलबदलू है। उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर बाकी जगह यही हाल है।

वायु सेना को मिलेंगे 114 राफेल- 94 विमानों का उत्पादन भारत में होगा

नई दिल्ली। भारत ने वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस को करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये के बड़े सरकारी समझौते का अनुरोध पत्र (एलओआर) भेज दिया है। यह रक्षा क्षेत्र में एक अहम कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विभाग ने यह अनुरोध पत्र फ्रांसीसी सरकार को भेजा। इस समझौते के तहत 114 में से 94 राफेल विमान भारत में बनाए जाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी डसॉ एविएशन एक भारतीय साझेदार कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों का निर्माण करेगी। सूत्रों के अनुसार, फ्रांस अगले दो से तीन महीनों में भारत के अनुरोध पत्र का जवाब दे सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी होने और समझौते को अंतिम रूप देने में करीब एक साल का समय लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के मध्य में फ्रांस की यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान फ्रांसीसी नेतृत्व के साथ होने वाली बैठकों में राफेल सौदे पर भी चर्चा होने की संभावना है। वायु सेना इस समय लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रनों की कमी का सामना कर रही है। इस कमी को दूर करने के लिए उन्नत 4.5 पीढ़ी के राफेल विमानों को बड़ी संख्या में शामिल करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

200 से अधिक हो जाएगी राफेल विमानों की संख्या

भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना पहले ही कुल 62 राफेल विमानों का ऑर्डर दे चुकी है। 114 नए विमानों के ऑर्डर के बाद देश में राफेल विमानों की संख्या 176 हो जाएगी। इसके अलावा, भारतीय नौसेना समुद्री खतरों से निपटने के लिए 31 और राफेल विमानों को शामिल करने की इच्छा जता चुकी है। अगर ऐसा होता है, तो भारत में राफेल विमानों की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी।

रक्षा मंत्रालय ने कराया था विस्तृत अध्ययन

2024 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कराया था। इसके बाद मंत्रालय इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने चार महीने पहले भारतीय वायु सेना के 114 राफेल विमानों की खरीद संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

वायु सेना प्रमुख का फ्रांस दौरा

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इस समय फ्रांस में है। वह डसॉ एविएशन की उन उत्पादन इकाइयों का भी दौरा कर सकते हैं, जहां राफेल विमान बनाए जाते हैं। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस के बाहर बनाए जाएंगे। इसमें करीब 50 प्रतिशत स्वदेशीकरण होगा, यानी कई हिस्सों और प्रणालियों का निर्माण भारत में किया जाएगा।

मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे राफेल विमान

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहले कहा था कि यह पहली बार होगा जब मेक इन इंडिया के तहत राफेल विमान फ्रांस के बाहर बनाए जाएंगे। यह सरकारों के बीच होने वाला समझौता होगा, जिसमें किसी बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। उन्होंने कहा था कि इस परियोजना में स्थानीय उत्पादन का स्तर काफी ऊंचा होगा और भारत को अपने हथियारों तथा स्वदेशी प्रणालियों को राफेल में एकीकृत करने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। इससे लड़ाकू विमानों की आपूर्ति भी अपेक्षाकृत जल्दी शुरू हो सकेगी।